VIRAT VAIBHAV, Delhi, 8.6.2025
Page No. 13, Size:(12.40)cms X (10.27)cms.

समग्र शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना: एनएचआरसी प्रमुख

वैभव न्यूज ■ भुवनेश्वर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा कि समग्र शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र को आकार देना और छात्र को आत्मनिर्भर बनाना है। न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने शुक्रवार शाम को यहां शिक्षा ओ अनुसंधान (मानद विश्वविद्यालय)में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी को चरित्र, मानसिक शक्ति और बुद्धि से सुसज्जित कर सके। उन्होंने कहा, शिक्षा को विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करना चाहिए, साथ ही उसकी बुद्धि का विकास करना चाहिए,

मानसिक शक्ति बढ़ानी चाहिए तथा उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाना चाहिए। एनएचआरसी के अध्यक्ष ने कहा कि आजकल अधिकांश छात्र शिकायत करते हैं कि वे तनावग्रस्त रहते हैं , यह एक ऐसा शब्द है, जो 40 साल पहले शायद ही कभी सुना जाता था। उन्होंने कहा कि इसका केवल इतना तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी को इतना लाड़-प्यार दिया गया है कि वे किसी भी समस्या का सामना करने में असमर्थ हैं। न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा, यह बताता है कि अच्छी शिक्षा और जरूरत की हर चीज उपलब्ध होने के बावजूद हम खुशहाल जीवन क्यों नहीं जी सकते। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में विफल रही है। उन्होंने कहा, आज सफलता ही मायने रखती है, लेकिन हम यह नहीं समझते कि सच्ची सफलता क्या है। शिक्षा पूरी कर लेना या बड़ी नौकरी पा लेना ही सफलता नहीं है। जीवन सफलता को उस तरह नहीं देखता, जिस तरह हम देखते हैं। एनएचआरसी प्रमुख ने सवाल किया, क्या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्रों को संकट प्रबंधन सिखाते हैं?

HINDUSTAN, Delhi, 8.6.2025
Page No. 1, Size:(21.09)cms X (11.48)cms.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

चिंताजनक : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों में कुपोषण के अधिक मामले सामने आए

कमजोर वर्ग के बच्चे और कमजोर हो रहे

एक्सक्लूसिव

■ प्रभात कुमार

नई दिल्ली। पिछले करीब दो दशक में देश में बच्चों के कुपोषण में कमी आई है। लेकिन कमजोर वर्ग के बच्चों में कुपोषण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ओर से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2019-21 में कुपोषण में 10 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, वर्ष 2015-16 के बाद बच्चों में उम्र और लंबाई के हिसाब से वजन कम होने और एनीमिया के मामले बढ़े हैं।

एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग के बच्चों में कुपोषण बढ़ा : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की तीन अलग-अलग रिपोर्ट से पता चलता है वर्ष 2015-16 में एससी के बच्चों में कुपोषण के मामले 60.6 फीसदी दर्ज किए गए थे जो 2019-21 में बढ़कर 70.3% हो गया। इसी तरह एसटी वर्ग के बच्चों में कुपोषण 63.3 से बढ़कर 73.9 फीसदी और ओबीसी वर्ग के बच्चों में यह आंकड़ा 58.6 फीसदी से बढ़कर 66.1 फीसदी हो गया। तीनों वर्गों में यह बढ़ोतरी लगभग 10-12 फीसदी तक देखने को मिली।

अन्य जातियों के मुकाबले अधिक कुपोषित: अन्य जातियों से तुलना करने पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों में कुपोषण के मामले अधिक मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-21 में एससी के बच्चों में बौनापन 39.2 फीसदी दर्ज किया गया, जबकि अन्य जातियों यह 29.6 फीसदी रहा। इसी अवधि में कुपोषण के मामले एससी और एसटी वर्गों में 70.3 फीसदी और 73.9 फीसदी दर्ज किया गया, जबकि अन्य जातियों में यह दर 66.5 फीसदी रही। इसी तरह वर्ष 2019-21 में बच्चों में कम वजन होने के मामले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग में 35.1 फीसदी, 39.5 फीसदी और 35.5 फीसदी रहा, जबकि अन्य जातियों में 26.3 फीसदी दर्ज किया गया। लंबाई के हिसाब से कम वजन के मामले में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चे अन्य जातियों की तुलना में कुपोषित मिले। यहां 19.7%, 23.2 फीसदी और 18.9% रहा, जबकि अन्य जातियों में 17.1% दर्ज किया गया।

खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अध्ययन: एनएचआरसी ने हिमाचल के केंद्रीय विश्वविद्यालय के जरिए देश में एससी-एसटी वर्ग के बच्चों में खाद्य और पोषण सुरक्षा के बारे में पता लगाने के लिए यह अध्ययन किया है। इसमें पांच महीने से लेकर पांच साल तक के उम्र वाले बच्चों का डाटा जुटाया गया। रिपोर्ट में चिंता जताई गई कि 2015-16 और 2019-21 के बीच की अवधि में बच्चों में उम्र के हिसाब से कम लंबाई होने और एनीमिया के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

10-12%
कुपोषण के केस एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के बच्चों में बढ़े

2015-16
के बाद बच्चों में उम्र और लंबाई के हिसाब से वजन कम होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में हुआ खुलासा
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया

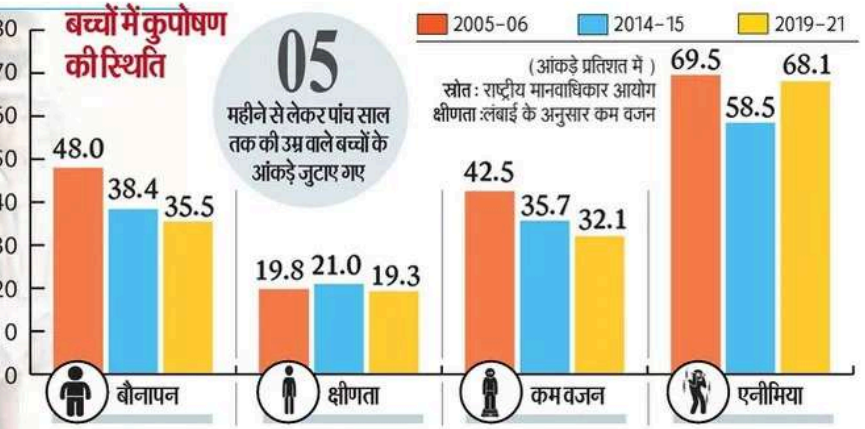

इन परिवारों में बौनापन अधिक

रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी से बाहर किए गए परिवार यानी जिनके पास जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की सुविधा नहीं है, उन परिवारों के बच्चों में बौनेपन की संभावना 43 फीसदी और कम वजन होने की संभावना 37 फीसदी अधिक है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में पीडीएस से बाहर रखे गए गरीब परिवारों में बौनेपन की संभावना काफी अधिक है।

एनएफएचएस के आंकड़े

एनएचआरसी की निगरानी में हुए अध्ययन के दौरान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के वर्ष 2005-06, 2014-15 और 2019-21 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। साथ ही फील्ड सर्वे भी किया गया।

PIONEER, Bhubaneswar, 8.6.2025
Page No. 3, Size:(24.90)cms X (12.36)cms.

'Environment and human rights are inseparable'

NALINI SAHU ■ Bhubaneswar

The vital connection between environmental conservation and human rights took centre stage at a special discussion organised to mark World Environment Day in Bhubaneswar on Thursday. The event, titled 'Environmental Protection and Human Rights', was jointly hosted by Evergreen Forum and Human Rights Front India at Geet Gobind Sadan.

Delivering the keynote address, Justice Dr. Bidyut Ranjan Sarangi, former Acting Chief Justice of High Court of Orissa and a member of the National Human Rights Commission (NHRC), highlighted how rising self-centred attitudes are jeopardising environmental efforts. "People often ignore how their relentless pursuit of material comforts negatively impacts both society and the environment. A balanced lifestyle is the key to sustaining a healthy planet," he observed.

Justice Sarangi described environmental protection as a shared responsibility, urging individuals, communities, and governments to actively participate in combating climate change, conserving natural resources, and adopting eco-friendly practices. He also paid tribute to forest officers who sacrifice their lives defending natural resources, calling them the "true martyrs" of environmental conservation.

Dr Padma Mahanti, DIG of Forests, Government of India, in her address, described a healthy environment as the "foremost human right." She stressed the need to prioritise environmental impact assessments in all development projects to safeguard ecosystems. Cautioning against irresponsible mining practices, she called for post-mining restoration initiatives and suggested transferring depleted mining sites to the Forest Department for rehabilitation.

Human Rights Front India president Manoj Jena, who chaired the session, flagged the severe human rights violations stemming from unchecked mining activities and demanded urgent action based on accurate assessments.

Guest of Honour, environmental scientist Dr Reena Routray warned that Mother Earth is in distress, advocating for drastic reduction in plastic use and collective action to reverse ecological damage.

DAINIK BHASKAR, Indore, 8.6.2025
Page No. 1, Size:(12.08)cms X (13.19)cms.

स्कूल, कॉलेज, संस्थानों में प्रदर्शित होगा टोल फ्री नंबर 14433

मानव अधिकार संबंधी शिकायतें दर्ज करवाना होगा आसान

डीबी स्टार, इंदौर।

प्रदेश सरकार ने स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक संस्थानों में अहम व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी स्कूल, अन्य शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों में मानव संसाधन विकास (एनजीओ व सिविल सोसायटी) की शिकायत निवारण हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर 14433 अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सिफारिशों को जमीनी स्तर पर लागू करने का एक प्रयास माना जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने भी जिला शिक्षा अधिकारियों और परियोजना समन्वयकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि एनएचआरसी के निर्देशों के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि मानव अधिकार संबंधी शिकायतों को दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जाए। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14433 को केंद्र सरकार और एनएचआरसी ने संयुक्त रूप से शुरू किया है, ताकि पीड़ित शिकायतें दर्ज करवा सकें और उन्हें जल्द मदद मिल सकें। यह सेवा विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते या जिन्हें डर व दबाव का सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था से मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया पारदर्शी और सुलभ बनेगी। इस तरह के मामलों की निगरानी में तेजी आएगी। छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ेगी कि अधिकारों के हनन की शिकायत कैसे करें। सरकारी संस्थानों में जवाबदेही भी बढ़ेगी, क्योंकि अब शिकायतें सीधे रिकॉर्ड पर होंगी। यह हेल्पलाइन बोर्ड सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों और कॉलेज, ब्लॉक और जिला शिक्षा कार्यालयों के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी लगेंगे।

HINDUSTAN, GAYA, 8.6.2025
Page No. 3, Size:(8.94)cms X (5.73)cms.

बच्चों के कुपोषण में 10% की कमी

■ प्रभात कुमार

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जारी रिपोर्ट में खुलासा
- 2005-06 की तुलना में 2019-21 में आई गिरावट
- 2015-16 के बाद बच्चों में उम्र और लंबाई के हिसाब से वजन कम होने के केस बढ़े

नई दिल्ली। पिछले करीब दो दशक में देश में बच्चों के कुपोषण में कमी आई है। वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2019-21 में कुपोषण में 10 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ओर से जारी शोध रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्ष 2015-16 के बाद बच्चों में उम्र और लंबाई के हिसाब से वजन कम होने और कमजोरी के मामले बढ़े हैं।

एनएचआरसी ने हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के जरिए देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में खाद्य और पोषण सुरक्षा के बारे में पता लगाने के लिए यह अध्ययन किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2005-06 से 2019-21 के बीच बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, 2005-06 में बच्चों में बौनापन (स्टंटिंग) 48 फीसदी था, जो 2019-21 में घटकर 35.5 फीसदी हो गया।

आंकड़ों का विश्लेषण

एनएचआरसी की निगरानी में हुए अध्ययन के दौरान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के वर्ष 2005-06, 2014-15 और 2019-21 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण से ये नतीजे सामने आए हैं।

HINDUSTAN, Agra, 8.6.2025
Page No. 1, Size:(21.09)cms X (11.51)cms.

चिंताजनक : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों में कुपोषण के अधिक मामले सामने आए

कमजोर वर्ग के बच्चे और कमजोर हो रहे

एक्सक्लूसिव

■ प्रभात कुमार

नई दिल्ली। पिछले करीब दो दशक में देश में बच्चों के कुपोषण में कमी आई है। लेकिन इस दौरान कमजोर वर्ग के बच्चों में कुपोषण के मामले बढ़ गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ओर से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2019-21 में कुपोषण में 10 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, वर्ष 2015-16 के बाद बच्चों में उम्र और लंबाई के हिसाब से वजन कम होने और एनीमिया के मामले बढ़े हैं।

एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग के बच्चों में कुपोषण बढ़ा: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की तीन अलग-अलग रिपोर्ट से पता चलता है वर्ष 2015-16 में एससी के बच्चों में कुपोषण के मामले 60.6 फीसदी दर्ज किए गए थे जो 2019-21 में बढ़कर 70.3% हो गया। इसी तरह एसटी वर्ग के बच्चों में कुपोषण 63.3 से बढ़कर 73.9 फीसदी और ओबीसी वर्ग के बच्चों में यह आंकड़ा 58.6 फीसदी से बढ़कर 66.1 फीसदी हो गई। तीनों वर्गों में यह बढ़ोतरी लगभग 10-12 फीसदी तक देखने को मिली।

अन्य जातियों के मुकाबले अधिक कुपोषित: अन्य जातियों से तुलना करने पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों में कुपोषण के मामले अधिक मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-21 में एससी के बच्चों में बौनापन 39.2 फीसदी दर्ज किया गया, जबकि अन्य जातियों यह 29.6 फीसदी रहा। इसी अवधि में कुपोषण के मामले एससी और एसटी वर्गों में 70.3 फीसदी और 73.9 फीसदी दर्ज किया गया, जबकि अन्य जातियों में यह दर 66.5 फीसदी रही। इसी तरह वर्ष 2019-21 में बच्चों में कम वजन होने के मामले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग में 35.1 फीसदी, 39.5 फीसदी और 35.5 फीसदी रहा, जबकि अन्य जातियों में 26.3 फीसदी दर्ज किया गया। लंबाई के हिसाब से कम वजन के मामले में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चे अन्य जातियों की तुलना में कुपोषित मिले। यहां 19.7%, 23.2 फीसदी और 18.9% रहा, जबकि अन्य जातियों में 17.1% दर्ज किया गया।

पांच महीने से पांच वर्ष तक के बच्चों पर अध्ययन: एनएचआरसी ने हिमाचल के केंद्रीय विश्वविद्यालय के जरिए देश में एससी-एसटी वर्ग के बच्चों में खाद्य और पोषण सुरक्षा के बारे में पता लगाने के लिए अध्ययन किया है। इसमें पांच महीने से लेकर पांच साल तक के उम्र वाले बच्चों का डाटा जुटाया गया। चिंता जताई गई कि 2015-16, 2019-21 के बीच की अवधि में बच्चों में उम्र के हिसाब से कम लंबाई होने और एनीमिया के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

गरीबी दर घटी पेज 15

10-12%
कुपोषण के केस एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के बच्चों में बढ़े

2015-16
के बाद बच्चों में उम्र और लंबाई के हिसाब से वजन कम होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में हुआ खुलासा
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया

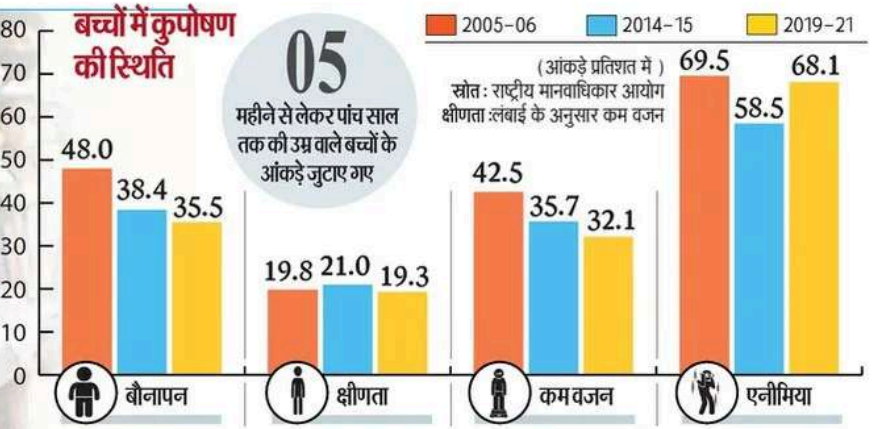

इन परिवारों में बौनापन अधिक

रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी से बाहर किए गए परिवार यानी जिनके पास जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की सुविधा नहीं है, उन परिवारों के बच्चों में बौनेपन की संभावना 43 फीसदी और कम वजन होने की संभावना 37 फीसदी अधिक है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में पीडीएस से बाहर रखे गए गरीब परिवारों में बौनेपन की संभावना काफी अधिक है।

एनएफएचएस के आंकड़े

एनएचआरसी की निगरानी में हुए अध्ययन के दौरान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के वर्ष 2005-06, 2014-15 और 2019-21 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। साथ ही फील्ड सर्वे भी किया गया।

The Week

NHRC chief emphasises on holistic education to make students self-reliant

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2025/06/07/ces8-od-nhrc-education.html

PTI Updated: June 07, 2025 14:09 IST

Bhubaneswar, Jun 7 (PTI) National Human Rights Commission (NHRC) Chairman Justice V. Ramasubramanian said the purpose of holistic education is to shape one's character and enable a student to become self-reliant.

Delivering a speech at the Siksha 'O' Anusandhan (Deemed to be University) here on Friday evening, he said the education system should be able to equip a student with character, mental strength and intellect.

"Education should form the character of a student while expanding his or her intellect, increasing the strength of mind and enabling the person to stand on his or her own legs," he said.The NHRC chairman said most students these days complained that they were "getting stressed out", a term rarely heard 40 years ago, which only referred to the fact that the present generation had been so pampered that they were unable to face any problem.

"This explains why we can't have a happy life even when we have a good education and everything we need," he said, adding that education had "failed" to strengthen the minds of students. "Today, it is success which matters, but we don't understand what true success is. Completing education or getting a big job does not mean success. Life does not look at success as we do," he said.

"Do colleges and universities teach students crisis management? People have degrees, but have they learned?" he asked.

The need is to "provide people the skill to face life and teach them the right attitude", he said. "A person may complete his or her course, but no one can complete education as it extends from the womb to tomb," he said.

(This story has not been edited by THE WEEK and is auto-generated from PTI)

Orissa Post

Education failed to strengthen minds of students: NHRC chief

https://www.orissapost.com/education-failed-to-strengthen-minds-of-students-nhrc-chief/

Post News Network | Updated: June 7th, 2025, 09:24 IST in Metro

Bhubaneswar: Education has failed to strengthen the minds of students, said National Human Rights Commission (NHRC) Chairman Justice V Ramasubramanian Friday. Delivering a talk at Siksha 'O' Anusandhan (SOA) Deemed to be University here, he observed that most students today often say they are 'getting stressed out', a term rarely heard 40 years ago.

This, he noted, pointed to the fact that the current generation has been so pampered that it struggles to face any problems. Justice Ramasubramanian emphasised that education should shape a student's character, expand their intellect, increase mental strength, and enable them to become self-reliant. "The purpose of holistic education is to develop the character of a person while fostering their physical, mental, moral, and spiritual growth," the NHRC Chairman stated. Quoting Swami Vivekananda, he highlighted that these four parameters — physical, mental, moral, and spiritual development — should guide education so that individuals can live happy and fulfilling lives. "A person may complete a course, but no one can complete education — it extends from the womb to the tomb," Justice Ramasubramanian said. Using several examples, the NHRC Chairman said the education system must equip students with character, mental strength, intellect, and self-reliance.

The NHRC Chairman cited philosopher and historian Will Durant's famous statement that education is 'the progressive discovery of one's ignorance', emphasising the importance of understanding this truth. "We have many literate people, but are we truly educated?" he asked, noting that colleges and universities only introduce students to the world's knowledge. "Today, success is all that matters. But we don't understand what true success is. Completing education or landing a big job does not mean success. Life does not view success as we do," the NHRC Chairman said. Justice Ramasubramanian narrated the story of a 45-yearold chartered accountant in the USA, who lost everything during the 2008 Global Financial Crisis. Unable to cope, he killed his entire family before taking his own life. "Despite his education and knowledge, he lacked the mental strength to face adversity," the NHRC Chairman said, adding, "Do colleges and universities teach students how to manage crises? People have degrees, but are they truly learned?" The real need, Justice Ramasubramanian emphasised, is to provide people with the skills to face life and to teach them the right attitude.

The Print Hindi

समग्र शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना: एनएचआरसी प्रमुख

https://hindi.theprint.in/india/aim-of-holistic-education-is-to-make-students-self-reliant-nhrc-chief/828012/

भाषा | 7 June, 2025 04:33 pm IST

भुवनेश्वर, सात जून (भाषा)राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा कि समग्र शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र को आकार देना और छात्र को आत्मनिर्भर बनाना है।

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने शुक्रवार शाम को यहां शिक्षा 'ओ' अनुसंधान (मानद विश्वविद्यालय)में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी को चरित्र, मानसिक शक्ति और बुद्धि से सुसज्जित कर सके।

उन्होंने कहा, "शिक्षा को विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करना चाहिए, साथ ही उसकी बुद्धि का विकास करना चाहिए, मानसिक शक्ति बढ़ानी चाहिए तथा उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाना चाहिए।"

एनएचआरसी के अध्यक्ष ने कहा कि आजकल अधिकांश छात्र शिकायत करते हैं कि वे "तनावग्रस्त रहते हैं", यह एक ऐसा शब्द है, जो 40 साल पहले शायद ही कभी सुना जाता था। उन्होंने कहा कि इसका केवल इतना तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी को इतना लाड़-प्यार दिया गया है कि वे किसी भी समस्या का सामना करने में असमर्थ हैं।

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा, "यह बताता है कि अच्छी शिक्षा और जरूरत की हर चीज उपलब्ध होने के बावजूद हम खुशहाल जीवन क्यों नहीं जी सकते।" उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में 'विफल' रही है। उन्होंने कहा,"आज सफलता ही मायने रखती है, लेकिन हम यह नहीं समझते कि सच्ची सफलता क्या है। शिक्षा पूरी कर लेना या बड़ी नौकरी पा लेना ही सफलता नहीं है। जीवन सफलता को उस तरह नहीं देखता, जिस तरह हम देखते हैं।"

एनएचआरसी प्रमुख ने सवाल किया, " क्या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्रों को संकट प्रबंधन सिखाते हैं? लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन क्या उन्होंने सीखा है?"

उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि "लोगों को जीवन का सामना करने का कौशल प्रदान किया जाए तथा उन्हें सही दृष्टिकोण सिखाया जाए।"

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा, "कोई व्यक्ति अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकता है, लेकिन कोई भी शिक्षा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेकर मरण तक चलती रहती है।"

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप

यह खबर 'भाषा' न्यूज़ एजेंसी से 'ऑटो-फीड' द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है

Janta Se Rishta

शिक्षा दिमाग को सशक्त बनाने में विफल: NHRC chief

https://jantaserishta.com/local/odisha/education-fails-to-empower-minds-nhrc-chief-4065015

June 7, 2025

Bhubaneswar भुवनेश्वर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षा छात्रों के दिमाग को मजबूत करने में विफल रही है। यहां शिक्षा 'ओ' अनुसंधान (एसओए) डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि आज के अधिकांश छात्र अक्सर कहते हैं कि वे 'तनावग्रस्त हो रहे हैं', एक ऐसा शब्द जो 40 साल पहले शायद ही सुना जाता था। उन्होंने कहा कि यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि वर्तमान पीढ़ी को इतना लाड़-प्यार दिया गया है कि वह किसी भी समस्या का सामना करने में संघर्ष करती है। न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने जोर देकर कहा कि शिक्षा को एक छात्र के चरित्र को आकार देना चाहिए, उनकी बुद्धि का विस्तार करना चाहिए, मानसिक शक्ति बढ़ानी चाहिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाना चाहिए। एनएचआरसी के अध्यक्ष ने कहा, "समग्र शिक्षा का उद्देश्य किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हुए उसके चरित्र का विकास करना है।"

स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन चार मापदंडों - शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास - को शिक्षा का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि व्यक्ति खुशहाल और पूर्ण जीवन जी सकें। न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा, "कोई व्यक्ति कोई कोर्स पूरा कर सकता है, लेकिन कोई भी शिक्षा पूरी नहीं कर सकता - यह गर्भ से लेकर कब्र तक फैली हुई है।" कई उदाहरणों का उपयोग करते हुए, NHRC के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को छात्रों को चरित्र, मानसिक शक्ति, बुद्धि और आत्मनिर्भरता से लैस करना चाहिए। NHRC के अध्यक्ष ने दार्शनिक और इतिहासकार विल डुरंट के प्रसिद्ध कथन का हवाला दिया कि शिक्षा 'किसी के अज्ञान की क्रमिक खोज' है, इस सत्य को समझने के महत्व पर जोर देते हुए। "हमारे पास कई साक्षर लोग हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में शिक्षित हैं?" उन्होंने पूछा, यह देखते हुए कि कॉलेज और विश्वविद्यालय केवल छात्रों को दुनिया के ज्ञान से परिचित कराते हैं। "आज, सफलता ही सब कुछ है।

लेकिन हम नहीं समझते कि सच्ची सफलता क्या है। शिक्षा पूरी करना या बड़ी नौकरी पाना सफलता का मतलब नहीं है। जीवन सफलता को उस तरह से नहीं देखता जैसा हम देखते हैं," NHRC के अध्यक्ष ने कहा। न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने यूएसए में एक 45 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट की कहानी सुनाई, जिसने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अपना सब कुछ खो दिया था। इससे निपटने में असमर्थ, उसने अपनी जान लेने से पहले अपने पूरे परिवार को मार डाला। एनएचआरसी के अध्यक्ष ने कहा, "अपनी शिक्षा और ज्ञान के बावजूद, उनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति की कमी थी।" उन्होंने आगे कहा, "क्या कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों को संकटों का प्रबंधन करना सिखाते हैं? लोगों के पास डिग्री तो होती है, लेकिन क्या वे वास्तव में विद्वान होते हैं?" न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने जोर देकर कहा कि वास्तविक आवश्यकता लोगों को जीवन का सामना करने के कौशल प्रदान करना और उन्हें सही दृष्टिकोण सिखाना है।

Hindustan

बच्चों के कुपोषण में 10 फीसदी से अधिक की गिरावट

प्रभात कुमार नई दिल्ली। पिछले करीब दो दशकों में देश में बच्चों के कुपोषण में कमी आई है। वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2019-21 में बच्चों के कुपोषण

https://www.livehindustan.com/ncr/new-delhi/story-significant-reduction-in-child-malnutrition-in-india-nhrc-report-201749303635361.html

प्रभात कुमार नई दिल्ली। पिछले करीब दो दशकों में देश में बच्चों के कुपोषण में कमी आई है। वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2019-21 में बच्चों के कुपोषण में 10 फीसदी से अधिक की कमी आई है। हालांकि 2015-16 के बाद बच्चों में उम्र और लंबाई के हिसाब से वजन कम होने और कमजोरी के मामले बढ़े हैं। इसका खुलासा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ओर से जारी शोध रिपोर्ट में हुआ है। एनएचआरसी ने हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के जरिए देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में खाद्य और पोषण सुरक्षा के बारे में पता लगाने के लिए यह अध्ययन किया है।

हाल ही में जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि '2005-06 से 2019-21 के बीच बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार हुआ है। इसमें कहा गया है कि बच्चों के कुपोषण की स्थिति में लगभग 10 फीसदी से अधिक का सुधार देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2005-06 में बच्चों में स्टंटिंग यानी बौनापन 48 फीसदी थी जो 2019-21 में घटकर 35.5 फीसदी रह गई। इसके साथ ही कहा गया है कि इसी अवधि के दौरान 42.5 फीसदी बच्चों में कम वजन होने की बात सामने आई थी, अब घटकर 32.1 फीसदी रह गया है। एनएचआरसी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों में बौनापन और वजह कम होने के मामले में 10 फीसदी से अधिक की कमी देखी गई है। एनएचआरसी की निगरानी में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्रो. डॉ. अमित कुमार बसंतराय और डॉ. इंदरवीर सिंह ने देखरेख में हुए इस अध्ययन में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के 2005-06, 2014-15 और 2019-21 के आंकड़ों का विश्लेषण करने के साथ ही, फील्ड सर्वे भी किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान वेस्टिंग यानी उम्र और लंबाई के हिसाब से बच्चों के कम वजह होने और एनीमिया की घटनाओं में केवल 0.5 और 1.4 फीसदी की कमी देखी गई। हालांकि रिपोर्ट में इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई है 2015-16 और 2019-21 के बीच की अवधि में बच्चों में वेस्टिंग और एनीमिया के मामलों में सुधार होने के बजाए गिरावट देखने को मिली है। 2015 15 में बच्चों में एनीमिया की दर 58.5 फीसदी थी जो 2019-21 में बढ़कर 68.1 फीसदी हो गई, जो कि लगभग 10 प्रतिशत से अधिक है। जिनके पास पीडीएस नहीं, उनके बच्चों में बौनेपन की संभावना अधिक रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी से बाहर किए गए परिवार यानी जिनके पास जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की सुविधा नहीं है, उन परिवारों के बच्चों में बौनेपन की संभावना 43 फीसदी और कम वजन होने की संभावना 37 फीसदी अधिक है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में पीडीएस से बाहर रखे गए गरीब परिवारों में बौनेपन की संभावना काफी अधिक है। एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों में मिले सबसे अधिक कुपोषण इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएफएचएस के तीनों रिपोर्टों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के बच्चों में कुपोषण के अधिक मामले देखने को मिले। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-21 में अन्य जातियों की तुलना में एससी

और एसटी के बच्चों में स्टंटिंग यानी बौनापन लगभग 10 फीसदी अधिक थी। अन्य जातियों की तुलना में इसी तरह, 2019-21 में एसटी के बच्चों में कम वजन होने के मामले 13.2 फीसदी और एससी के बच्चों में 9.8 फीसदी अधिक थी। हालांकि इन समुदायों के बच्चों में उम्र और लंबाई के हिसाब से कम वजन और कमजोरी की शिकायत अपेक्षाकृत कम था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी और एसटी के बच्चों में 2005-06 में 53 फीसदी था जो घटकर 2019-21 में लगभग 40 फीसदी रह गया। इसी अवधि के दौरान, एससी और एसटी के बीच कम वजन की घटना 12.9 और 15.2 फीसदी कम हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य जातियों की तुलना में एससी और एसटी के बच्चों के बाद सबसे अधिक ओबीसी के बच्चों में कुपोषण देखने को मिली है। बच्चों में कुपोषण के आंकड़े आंकड़े वर्ष बौनापन वेस्टिंग कम वजन कमजोरी 2005-06 48.0 19.8 42.5 69.5 2014-15 38.4 21.0 35.7 58.5 2019-21 35.5 19.3 32.1 68.1

The Hans India

AP has become a lawless State under coalition govt rule: Sajjala

https://www.thehansindia.com/amp/andhra-pradesh/ap-has-become-a-lawless-state-under-coalition-govt-rule-sajjala-977927

The Hans India | Update: 2025-06-08 06:33 IST

Andhra Pradesh government advisor Sajjala Ramakrishna Reddy Guntur: YSRCP State coordinator Sajjala Ramakrishna Reddy has lashed out at the Chandrababu Naidu-led NDA government, alleging that a section of police officers was acting like a private army for CM Chandrababu Naidu and Minister Nara Lokesh. He said an organised crime gang has been created within the police system, causing grave harm to the State's law and order machinery.

Speaking to the media after visiting Lakshminarayana, a YSRCP worker receiving treatment at a private hospital in Guntur on Saturday, he demanded strict action against the DSP who harassed him and called for a judicial inquiry by a sitting judge into the incident.

He also announced that complaints on State-sponsored violence would be submitted to the President of India and the National Human Rights Commission (NHRC).

Referring to a past NHRC remark on Uttar Pradesh, which called the police force there an "Organised crime gang in uniform," he said that AP was currently witnessing a far worse situation.

He detailed how Lakshminarayana, a businessman and party activist, was summoned by the DSP under the pretext of a panchayat. Sajjala alleged that the YSRCP activist was verbally abused with caste-based slurs, and humiliated for his political affiliation. The emotional distress led him to attempt suicide, and he was now battling for life.

ysrcongress

AP turned into a lawless state under the TDP rule

https://www.ysrcongress.com/top-stories/ap-turned-lawless-state-under-95630

07 Jun 2025 4:51 PM

Guntur, June 7: YSRCP State Coordinator Sajjala Ramakrishna Reddy has lashed out at the Chandrababu Naidu-led TDP government, stating that a section of police officers is acting like a private army for CM Chandrababu Naidu and Minister Nara Lokesh. He said an organized crime gang has been created within the police system, causing grave harm to the state's law and order machinery.

Speaking to the media after visiting Lakshminarayana, a YSRCP worker receiving treatment at a private hospital in Guntur, Sajjala demanded strict action against the DSP who harassed him and called for a judicial inquiry by a sitting judge into the incident. He also announced that complaints on state-sponsored violence would be submitted to the President of India and the National Human Rights Commission (NHRC). Referring to a past NHRC remark on Uttar Pradesh, which called the police force there an “organized crime gang in uniform,” Sajjala warned that Andhra Pradesh is now witnessing a far worse situation, with unchecked police actions pushing the state toward institutional collapse.

Lakshminarayana case – a disturbing abuse of power:

Sajjala detailed how Lakshminarayana, a businessman and party activist, was summoned by a DSP under the pretext of a panchayat, verbally abused with caste-based slurs, and humiliated for his political affiliation. The emotional distress led him to attempt suicide, and he is now battling for life. Sajjala compared this to the Emergency era and blamed the Chandrababu government for destroying the friendly policing culture brought in under YS Jagan’s leadership.

Sajjala described the current situation as a silent, undeclared Emergency, where police are misusing legal powers as tools of oppression, unchecked by accountability or oversight. He cited several disturbing incidents across the state like Kidnapping of Satavahana College principal by a TDP MLC, beating of three youth in Tenali in broad daylight, custodial torture of a young man, Harikrishna, in Palnadu and harassment of women activists like Sudharani and Krishnaveni, who were intimidated without arrests or due process.

He expressed concern that even law-abiding officers are being targeted and pushed into VR, while violators enjoy protection from ministers. “This is not law and order—it is sponsored anarchy,” he said.

Sajjala concluded that YSRCP will not stay silent, and will pursue the matter in courts, human rights forums, and before the people, to restore democratic values and protect citizens from state abuse.

Deccan Herald

Dakshina Kannada crackdown: Keep politics out

Political interference must not be allowed to derail police action to restore peace in the district

https://www.deccanherald.com/opinion/editorial/dk-crackdown-keep-politics-out-3575274

DHNS Last Updated : 07 June 2025, 04:31 IST

Two back-to-back murders in Dakshina Kannada, each laced with communal undertones, have finally jolted the government to action. Police officers are now cracking down on lumpen elements across communities – a much-needed move to restore order. The government has rightly overhauled the police top brass in Dakshina Kannada and neighbouring Udupi, signalling a firm resolve to address the escalating communal tensions. But even as law enforcement begins to act decisively, Union Minister of State for Labour and Employment Shobha Karandlaje has chosen a troubling path. She has written to Justice N K Sudhindra Rao, chairman of the Police Complaints Authority, alleging police harassment of “innocent” Hindu activists. A copy of the letter has also been marked to the National Human Rights Commission.

Karandlaje’s complaint is both misplaced and misleading. As a constitutional authority, she should stand by the law, not those who flout it. The police have been doing their duty in a district teetering on the edge. Her letter, devoid of specifics, amounts to a blatant interference in the enforcement of law and order. The claim that GPS tracking is being used to target Hindutva activists holds no water – modern technology tools are legitimate instruments to track criminal suspects irrespective of their religious identity. Who exactly are these “innocent” people she wants to shield? Many are known offenders. For instance, Suhas Shetty whose recent murder sparked outrage was a rowdy sheeter with two murder charges against him, all booked when BJP was in power. Karandlaje’s portrayal of police action as one-sided is factually incorrect. The list of anti-social elements who the police propose to extern from the district includes those from both Hindu and Muslim communities. Such interference from a union minister not only undermines the police action to restore peace but also sends dangerous signals that political patronage can shield anti-social elements from the due process of law. The Prime Minister should take serious note of this.

The police must be allowed to continue their operations unhindered. They should act even against those occupying top positions if they engage in hate speech or incite violence. Politicians who poison the minds of the youth and use them as pawns for narrow electoral gains, while their children study abroad, should be held accountable.

The state government must back the police not just with moral support, but with robust legal resources that ensure that these criminals don’t get a reprieve from the court. The coastal districts need healing and that will happen only when politicians stop stoking fires, and allow the law to take its course. Karnataka News Karnataka Dakshina Kannada Opinion Editorial

The Federal

How social media is giving wings to upward mobility dreams, spurring sexual abuse

https://thefederal.com/the-federal-special/social-media-sexual-exploitation-upward-mobility-190924

Ranjit Bhushan 8 June 2025 6:30 AM (Updated:8 June 2025 6:31 AM)

In Bihar's Saran district, a relatively remote location given the intensity of the crime, 162 minor girls have been rescued this year alone from troupes masquerading as orchestra-and-dance teams. Investigators say the troupes were barely concealed fronts used to force the girls into prostitution.

The minor girls were typically lured with the promise of money and employment coupled with the biggest enticement of them all – two-minutes of fame on social media platforms like Instagram and Facebook.

According to Saran Superintendent of Police (SP) Kumar Ashish, the "girls were being forced to dance in orchestras and were subjected to inappropriate acts."

Of those rescued, eight were from West Bengal, four from Odisha, two from Jharkhand and Delhi, and one from Bihar, the SP said, adding that the operation was led by the Women's Police Station and conducted with support of local police teams and members of non-profit organisations such as Mission Mukti Foundation, Rescue Foundation (Delhi) and Narayani Sewa Sansthan (Saran).

Trafficking via social media

Dance troupes are a popular conduit, but by no means the only ones. Meeting online is the real killer. Amid a rise in trafficking cases in the National Capital Region (NCR), to name just one territory, several instances have come to light where gullible victims are increasingly trapped through social media platforms.

In another well-publicised case, a 14-year-old from West Bengal, met a trafficker online on one such platform and began chatting. It turned out to be more than mere harmless chit-chat. After gaining this underage girl's trust, the trafficker persuaded her to leave home and whisked her away to sell her to a 'safehouse' in the national capital. The teen was rescued from Delhi recently, weeks after being trafficked to the city.

"Social networking websites have recently developed into a popular tool that men and traffickers use to approach young girls without any boundaries and entice them with the promise of better opportunities and coerce them into sexual exploitation. To educate young girls about the various methods that human traffickers use to conceal their identities, to entice them, and coerce them into exploitation, schools should implement a

curriculum on cyber-enabled human trafficking cases. It is important to raise awareness among children," Rishi Kant, activist and member of Shakti Vahini, told the media.

Internet spurs upward mobility

India's infatuation with the internet is staggering. In early 2025, India had an estimated 806 million internet users, representing 55.3 per cent of the population. Projections indicate this number will continue to grow, with some reports suggesting India could surpass 900 million internet users by the end of 2025. This growth is being driven by increasing access in rural areas and the adoption of Indic languages for online content.

This combination works in total sync. India is one of the youngest countries in the world, and 65 per cent of its estimated 1.464 billion population is below 35.

In such a gigantic digital ecosystem, where children are increasingly exposed to online platforms, the prevalence of online child sexual abuse and exploitation poses a significant threat to their safety and well-being.

While social mobility in India is, without doubt, opening new frontiers, offering the promise of upward mobility, it is not without its downsides. For many, particularly in the lower castes or classes of society, it is exacerbating vulnerabilities, making individuals, with stars in their eyes, susceptible to sexual exploitation in various contexts.

Individuals, particularly from unprotected backgrounds, may be forced to seek work or support from exploitative individuals or institutions to climb the social ladder. Migrants or individuals moving to urban areas in search of opportunities find a whole new life online – a life which they know very little about. Once caught up in the vicious cycle, they may lack the social networks and support systems that can protect them from exploitation, both sexual and economic.

More takers for child sexual abuse content

The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken Suo motu cognisance of a media report of 2023, which claimed that the circulation of Child Sexual Abuse Material (CSAM) had increased by 250 to 300 per cent on social media in India.

"The Commission has observed that the content of the media report, if true, amount to a violation of human rights relating to the life, liberty, and dignity of citizens, and protection of the young children from the danger of their sexual abuse on social media. Accordingly, it has issued notices to the Commissioner of Police, Delhi, the Director Generals of the Police of all the States/UTs, the Director, the National Crime Record Bureau (NCRB), and the Secretary, the Union Ministry of Electronics and Information Technology, calling for a detailed report in the matter within 6 weeks on the steps taken to prevent such menace on social media," the report by the commission said.

Given the magnitude of the problem, certain key recommendations are in order. They include mandatory reporting of online child sexual abuse, due diligence by internet service

providers (ISPs), and the establishment of log retention periods to facilitate effective cybercrime investigations.

Comprehensive approach must to fight crime

What is also considered obligatory is a comprehensive approach involving parents, lawmakers, non-governmental organisations (NGOs), and law enforcement agencies that is essential for combating online child sexual abuse. Crucially, leveraging new technological solutions and signing international conventions is proposed to enhance cooperation and improve prosecution efforts across borders.

There is also the urgent need to focus on the multifaceted issue of online child sexual abuse and exploitation, focusing on interpersonal cybercrimes and the legal provisions in India aimed at combating these offences. It highlights the vulnerabilities faced by children in digital environments, particularly exacerbated by the COVID-19 pandemic, which has led to a surge in internet usage among young users.

The path ahead is littered with thorns, even for those who may be well intentioned. Technological advancements, such as encrypted messaging platforms and peer-to-peer networks, have made detecting and prosecuting offenders increasingly difficult. The existing legislations in India have several significant gaps, thereby limiting the effective protection for children in the digital realm.

Deadly cocktail

It is not as if the Supreme Court is not seized of the matter. In September last year, it asked social media intermediaries to observe due diligence, which included not only the removal of child pornographic content but also making an immediate report of such content to the concerned police units in the manner specified under the (Protection of Children from Sexual Offences) POCSO Act.

The apex court also said social media intermediaries, in addition to reporting the commission or the likely apprehension of commission of any offence under POCSO to the National Centre for Missing & Exploited Children (NCMEC), is also obligated to report the same to authorities specified under Section 19 of POCSO i.e., the Special Juvenile Police Unit (SJPU) or the local police.

Clearly the lines are drawn. But the gargantuan spread of the internet, coupled with vulnerability of the weaker sections and an upward mobility that a growing economy spawns, is a deadly cocktail. Getting a handle on this volatile mix is going to be a challenge for all stakeholders.

Ranjit Bhushan is an independent journalist and author. In 2016, he published a book titled 'Maoism in India and Nepal'.

The New Indian Express

Salwa Judum case: Legislative workaround and limits of contempt power

https://www.newindianexpress.com/explainers/2025/Jun/07/salwa-judum-case-legislative-workaround-and-limits-of-contempt-power

Manish Kumar | Updated on: 08 Jun 2025, 12:42 am

4 min read

The doctrine of separation of powers must always be acknowledged in a constitutional democracy, the Supreme Court said in its May 15 order ruling that any law made by Parliament or state legislatures cannot be held to be in contempt of court. The decision by a bench of Justices B V Nagarathna and Satish Chandra Sharma came while dismissing a 2012 contempt petition filed by sociologist Nandini Sundar and others against the Chhattisgarh government for enacting the Auxiliary Armed Police Force Act, 2011, alleging the law violated an earlier SC order. The bench held that the law did not amount to contempt of the SC's 2011 landmark judgment that disbanded the state government-backed Salwa Judum, terming it unconstitutional. Salwa Judum was a government-backed militia formed in Chhattisgarh in 2005, which used armed tribal civilians to combat Maoist violence.

The contempt plea claimed that the Chhattisgarh government failed to comply with the 2011 order to stop open backing of vigilante groups like the Salwa Judum, and instead went ahead and armed tribal youths in the fight against Maoists. It said there had been a clear contempt of the SC order when the state government passed the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force Act, 2011, which legalised arming tribals in the form of Special Police Officers (SPOs) in the war against Maoists.

The petitioners further submitted that instead of disarming SPOs, which was a key constituent of the SC's 2011 order, the Chhattisgarh government legalised the practice of arming them. They also argued that the victims of the Salwa Judum movement had not been adequately compensated.

In the latest ruling of May 15, the Supreme Court said the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force Act, 2011 does not constitute a contempt of court per se, and that the balance between sovereign functionaries must always be delicately maintained. "Every State Legislature has plenary powers to pass an enactment and so long as the said enactment has not been declared to be ultra vires the Constitution or, in any way, null and void by a Constitutional Court, the said enactment would have the force of law," the bench said. If any party wants that the legislation be struck down for being unconstitutional, the legal remedies would have to be presented before an appropriate constitutional court, the bench noted.

Salwa Judum: A Vigilante Movement

In 2005, Chhattisgarh witnessed the emergence of Salwa Judum, a state-sponsored vigilante movement aimed at countering the Maoist insurgency. The movement, led by Congress MLA Mahendra Karma, was initially supported by local traders and business community, and soon received backing from the state government.

However, Salwa Judum's methods were marked by violence and human rights abuses, with villagers and tribal people being herded into makeshift camps. The movement's actions led to large-scale displacement, with over 100,000 civilians, as per one report, fleeing to camps or neighbouring states. The movement led to significant loss of life and property.

A fact-finding team's account in an essay titled ‘Salwa Judum: War in the Heart of India' by the Independent Citizens Initiative stated that many tribal youths, many unwilling, were drafted in as SPOs for paltry salaries. “Many SPOs complained that while they had been enlisted in the service of the nation to rid the area of Maoist menace, they had not been trained in weapons use and could not even defend themselves let alone rid the area of Maoists. Many were armed with bows and arrows, or with obsolete World War II vintage 303 rifles. The government was unwilling to arm them with better weapons for fear they could fall into the hands of Maoists. On the other hand, they are vulnerable to Maoist counter attacks.”

By 2008, Salwa Judum’s influence began to wane, with the number of people living in camps dwindling and public support decreasing. The group was accused of human rights abuses, including killings, abductions, and rapes. The National Human Rights Commission (NHRC), which launched the fact-finding mission, said the movement had lost momentum, restricting itself to 23 camps in Dantewada and Bijapur districts. Chhattisgarh police's experiment to employ tribal youths as SPOs, or Koya Commandos, seemed to have backfired

Times of India

Unruly act, emotional assault, says IMA on health minister's outburst

https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/unruly-act-emotional-assault-says-ima-on-health-ministers-outburst/articleshow/121700457.cms

TNN | Jun 8, 2025, 01.44 AM IST

Panaji: The Indian Medical Association's Goa branch on Saturday said it was "deeply disturbed" and "profoundly disappointed" by a video in which health minister Vishwajit Rane is seen yelling at a doctor in front of a camera crew before ordering his suspension. The IMA called it an "emotional assault on the doctor", and urged authorities to immediately rescind the suspension and reinstate him.The association strongly condemned the "unacceptable" and "unruly act" by the health minister. It stood firmly with the victimised doctor, and stated that Rane's actions were "deeply regrettable and unacceptable". "It not only bypasses due process and natural justice, but also disregards the professional dignity and morale of the entire medical community," the association stated.

"We strongly condemn this arbitrary and high-handed behaviour that has humiliated and victimised a dedicated medical professional in full view of the public and media," said IMA-Goa state president, Dr Dattaram Dessai, in a press note.

"IMA Goa firmly believes that any grievance, no matter how serious, should be addressed through a fair, transparent, and structured inquiry," the association stated. "Proceeding to suspend a senior doctor from the emergency department without giving him an opportunity to present his side of the facts, besides publicly berating him in tone and manner, amounts to an emotional assault on the duty doctors."

The Federation of All India Medical Association (FAIMA doctors association), in a letter to the chief minister copied to the Prime Minister, Union health minister, IMA, National Human Rights Commission and National Medical Council, has threatened a nationwide agitation including mass protests, in solidarity with GMC doctors if no immediate public apology comes from the health minister.

The federation also expressed "deep anguish and unflinching condemnation" at the doctor being publicly humiliated and verbally assaulted for exercising his clinical judgement in declining a non-emergent B 12 injection requested by an acquaintance of the minister. "No doctor should be expected to violate medical norms under pressure from political figures or VIP acquaintances," it said.

The Indian Radiological and Imaging Association's Goa chapter also "strongly condemned" Rane and his "uncalled-for, abusive, and condescending behaviour" towards the doctor. The association said that the incident creates a precedent to normalise hostility towards medical professionals.

“It is absolutely unacceptable that a chief medical officer on duty is subjected to verbal abuse and public humiliation in the presence of media, civilians, patients and hospital staff, with no admission of statement from the doctor,” it said.

The Wire

Seven Maoist Leaders Killed in 3-Day `Encounter': Rights Groups Allege Brutal Torture

https://thewire.in/rights/bijapur-encounter-maoists-killed-chhattisgarh-sudhakar-bhaskar

N. Rahul | 13 hours ago

5 min read

The encounters took place amidst claims by civil rights organisations that the police had picked up 10 Maoists from Parshagarh village from the 1,250 square-kilometre national park where they were sheltered.

Hyderabad: Encounters have been on between security forces and Maoists at the Indravati National Park in Bijapur district of Chhattisgarh for three consecutive days from June 5. Seven Maoist leaders have been killed.

The encounters took place amidst claims by civil rights organisations that the police had picked up 10 Maoists from Parshagarh village from the 1,250 square-kilometre national park where they were sheltered.

Rights bodies have said that seven of them were killed in cold blood after inhuman torture on a daily basis – one on June 5, four on June 6 and two on June 7. Three more Maoists are in police custody, the Civil Liberties Committee's Telangana president Gaddam Laxman, general secretary M. Narayana Rao and other office bearers said.

Even as the police said that only two dead bodies have been identified so far, rights activists have released the names of ten Maoists who were in police custody. The names include those of CPI (Maoist) central committee member Tentu Laxmi Narasimha Chalam alias Sudhakar who was killed on June 5 and CPI (Maoist) Telangana state committee member Mylarapu Adelu alias Bhaskar, who was killed on June 6. They were also the only names confirmed by police as dead.

Additionally, Laxman said they learnt about the death of another Telangana state committee member Bandi Prakash and Dandakaranya special zonal committee member Papa Rao on June 7. Those in police custody include divisional committee member Ramanna, national park area committee secretary Dilip, Dandakaranya area committee woman secretary Situ, and national park area committee members Sunita, Mahesh and Munna.

Differing versions

Laxman had also issued a press release on the evening of June 5, apprehending danger to the lives of Prakash and others in police custody. He demanded their immediate production in court without any harm coming to them. He also called on the Union government to announce a ceasefire and hold peace talks with Maoists.

A press release issued by Bijapur superintendent of police Jitendra Kumar said the dead included two unidentified women and three men.

Laxman told media persons that 10 Maoists in civil dress, abandoning their olive green uniforms, took shelter in Pashagarh village on June 5 when police learnt about their presence through its informant network. Quoting villagers, he added that the police arrived to take them away at around 7 am. They were then reportedly shot dead one after another. He asked the National Human Rights Commission and the Supreme Court to launch suo motu proceedings against the police.

Speaking to The Wire, SP Yadav denied the allegations of the activists and called it false propaganda. He said the operation was launched on specific information that Sudhakar, Bandi Prakash and Papa Rao were among a group of Maoists gathered in the national park area. Joint troops of Special Task Force, District Reserve Guard and CoBRA were dispatched to comb the forest, said the SP.

Sudhakar was killed in the exchange of fire on the first day and an AK-47 rifle was recovered from the site, he claimed. He also called this another big success for the police after the killing of Maoist party general secretary Nambala Kesava Rao in Narayanpur district on May 21.

Four more Maoists were killed on the morning and late night of June 6, including Bhaskar. and two on June 7, Yadav said. Efforts were underway to establish the identity of five bodies of Maoists other than Sudhakar and Bhaskar, he added.

Yadav expressed dismay that the rights organisations had revealed the identity of the slain Maoists and said that he himself was unaware of it.

Some security personnel suffered injuries in the crossfire and some due to snakebite. A few also suffered dehydration, he said.

‘A constitutional crisis’

The Coordination Committee for Peace, comprising mediator G. Haragopal and others, said that 18 senior leaders of CPI (Maoist) were in police custody. They noted that these leaders faced grave threats to their lives from police. “The constitutional crisis unfolding in Chhattisgarh demanded urgent intervention by the court to prevent further erosion of democratic principles and protection of fundamental rights,” they said.

Haragopal had mediated with Maoists to secure the release of collectors Alex Paul and Vinyl Krishna when they were kidnapped in the past in Chhattisgarh.

Today’s killings marked the continuation of fresh hostilities launched by police.

Sudhakar was part of a Maoist delegation that held peace talks with the Y.S. Rajasekhara Reddy government in the undivided Andhra Pradesh in 2004. Sudhakar was also in charge of the regional bureau of Revolutionary Political School run by the CPI (Maoist).

Sudhakar also had a two-tier security cover from the party. Rights activists thus argue that if he was killed in a genuine encounter, his security guards would also have fallen to the bullets. But it was only his body that was recovered from the site. They reminded that he was seen in civil clothing instead of military fatigues worn by armed cadre like him. Sudhakar had led an underground life for 40 years after dropping out from Ayurveda college in Vijayawada.

Bhaskar, on the other hand, was a registered medical practitioner at Ramakrishnapur in erstwhile Adilabad district. He joined the then people's war in 1995.

The Committee for Release of Political Prisoners headed by Balla Ravindranath has also alleged that Sudhakar and Bhaskar were killed in fake encounters. A member of Indian Association of People's Lawyers Pichuka Sudhakar addressed a letter to the Chief Justice of Chhattisgarh high court to issue orders for preservation of their bodies until another post mortem examination was conducted.

The Civil Liberties Committee general secretary Laxman Rao said 550 Maoists have lost their lives in Operation Kagar of the Union government from January 1 last year. About 400 of them were poor tribals, they said. The operation was aimed to scuttle the struggles of tribals to hand over mineral wealth in Chhattisgarh to corporates, the group claimed.

Dynamite News

महराजगंज में पुलिस की लापरवाही उजागर: जिंदा किशोरी को मृत बताकर पिता और भाई को भेजा जेल, NHRC ने मुकदमा दर्ज करने का दिया निर्देश

जीवित किशोरी को मृत बता कर उसी के पिता और भाई को जेल भेजने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पूरी खबर के लिए पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़

https://hindi.dynamitenews.com/uttar-pradesh/police-negligence-exposed-in-maharajganj-father-and-brother-sent-to-jail-after-declaring-a-live-teenager-as-dead-victim-approached-nhrc

7 जून 2025

महराजगंज: घुघली थाना क्षेत्र से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह मामला वर्ष 2023 का है, जब एक किशोरी के लापता होने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया और हत्या के झूठे आरोप में उसके पिता और भाई को जेल भेज दिया गया। अब जब उक्त किशोरी बिहार के बगहा में जीवित पाई गई, तो पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आई और पुलिस की लापरवाही उजागर हो गई।

ये है पूरा मामला

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार मामले की शुरुआत तब हुई जब घुघली क्षेत्र की किशोरी काम पर गई लेकिन वापस नहीं लौटी। उसके पिता संजय ने गांव के तीन लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच निचलौल क्षेत्र की नहर में एक अज्ञात युवती का शव मिला, जिसे पुलिस ने बिना डीएनए परीक्षण के संजय की बेटी प्रीति मान लिया। हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस ने संजय और उनके बेटे अम्बरीश उर्फ सूरज को जेल भेज दिया। लेकिन कुछ समय बाद वही कथित मृत लड़की बिहार के बगहा में जीवित पाई गई।

पिता ने लिया मानव अधिकार आयोग का रुख

इस घटना से मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हुए पीड़ित संजय ने जब उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का रुख किया, तो आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और जांच कर गंभीर लापरवाही उजागर की। आयोग ने तत्कालीन थानाध्यक्ष नीरज राय और विवेचक वरिष्ठ उप निरीक्षक भगवान बक्श सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

आयोग ने की कार्रवाई की संस्तुति

इसके साथ ही, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. आदीदेव पर भी डीएनए नमूना संरक्षित न करने की लापरवाही पाई गई, जिसके लिए आयोग ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। वहीं, तत्कालीन सीओ सदर अजय सिंह चौहान को भी अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाह मानते हुए शासन को उनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

आयोग ने की पीड़िता को एक-एक लाख रुपए देने की सिफारिश

आयोग ने पीड़ित पिता संजय और उनके पुत्र को एक-एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश भी की है, साथ ही यह स्पष्ट किया है कि इस धनराशि की वसूली संबंधित लापरवाह अधिकारियों से की जाए। इस घटना ने पुलिस प्रशासन की जांच प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह उदाहरण बन गया है कि किसी की लापरवाही निर्दोष लोगों को कितना बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है।

Prabhat Khbar

Saran News : आवाज दो अभियान के तहत आर्केस्ट्रा से 21 नाबालिग नर्तकियों को कराया गया मुक्त

Saran News : सारण एसएसपी डॉ कुमार आशीष के निर्देश पर आवाज दो अभियान के तहत जिला पुलिस लगातार ऑर्केस्ट्रा ग्रुप पर छापेमारी कर नाबालिक लड़कियों को मुक्त करा रहा है.

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/saran/21-minor-dancers-were-made-to

By ALOK KUMAR | June 7, 2025 9:28 PM

छपरा. सारण एसएसपी डॉ कुमार आशीष के निर्देश पर आवाज दो अभियान के तहत जिला पुलिस लगातार ऑर्केस्ट्रा ग्रुप पर छापेमारी कर नाबालिक लड़कियों को मुक्त करा रहा है. इसी क्रम में शनिवार क़ो जिला के मढौरा, खैरा, तरैया एवं अमनौर थाना क्षेत्र में टीम बनाकर छापेमारी की गयी जहां से कुल 21 नाबालिक नर्तकियों को मुक्त कराया गया, जिसमें 15 बंगाल की रहने वाली है. जबकि तीन आसाम, एक उत्तर प्रदेश एवं दो बिहार की रहने वाली नर्तकियां शामिल है. वही छापेमारी के दौरान तीन ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार की भी किया गया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त सूचना के आधार पर मिशन मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली, नारायणी सेवा संस्थान छपरा एवं रेस्क्यू फाउंडेशन वेस्ट बंगाल के साथ आवाज दो टीम के द्वारा जिले के मढौरा, खैरा, तरैया एवं अमनौर थाना क्षेत्र में टीम बनाकर छापेमारी की गयी. जहां से कुल 21 नाबालिक नर्तकियों को मुक्त कराया गया, जिसमें 15 बंगाल की रहने वाली है. जबकि तीन आसाम, एक उत्तर प्रदेश एवं दो बिहार की रहने वाली नर्तकियां शामिल हैं. उक्त मामले मंस महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. विदित हो कि जिले में लगातार आर्केस्ट्रा संचालकों के चंगुल से नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया जा रहा है. वहीं सारण पुलिस के द्वारा आवाज दो अभियान चला कर लड़कियों एवं महिलाओं के शोषण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. वहीं नाबालिक लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा संचालकों के चंगुल से मुक्त कराया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Chapra Today

आर्केस्ट्रा से 21 नाबालिग लड़कियों को कराया गया मुक्त, 3 संचालक गिरफ्तार

https://chhapratoday.com/chhapra/21-minor-girls-rescued-from-orchestra-3-operators-arrested/

CT Central Bureau

Chhapra: एसएसपी डॉ कुमार आशीष के निर्देश पर विभिन्न थानों के टीम आज अहले सुबह छापामारी कर 21 नाबालिग लड़कियों को आर्केस्ट्रा से मुक्त कराया गया । इसके साथ ही 3 आर्केस्ट्रा संचालक को गिरफ्तार किया गया।

मई-2024 से अबतक के विशेष अभियान में कुल 188 लड़कियों को मुक्त कराकर 23 कांड दर्ज करते हुए 61 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

सारण पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष के निर्देश पर महिला थाना द्वारा टीम गठित कर मढ़ौरा, खैरा, तरैया एवं अमनौर थानान्तर्गत आर्केस्ट्रा का विधिवत घेराबंदी कर छापामारी किया गया।

इस क्रम में जबरन प्रताड़ित कर आर्केस्ट्रा में नृत्य करवाये जाने वाली 21 नाबालिग लड़कियों (जिनमें पश्चिम बंगाल-15, असम-03, उत्तर प्रदेश-01 एवं बिहार-02) को मुक्त कराया गया तथा 03 आर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में महिला थाना कांड सं0-50/25, दिनांक-07.06.2025 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

मई-2024 से अबतक सारण जिलान्तर्गत कुल-188 लड़कियों को अनैतिक देह व्यापार से मुक्त कराकर 23 कांड दर्ज करते हुए 61 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शेष अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

अजीत कुमार उर्फ बिल्ला, पिता-संजय प्रसाद, साकिन-कॉलेज रोड, अमनौर, थाना-अमनौर, जिला-सारण।

रवि कुमार ठाकुर, पिता-स्व० राम प्रसाद ठाकुर, साकिन गंगापुर, थाना-मुसरीघरारी, जिला-समस्तीपुर।

विकास शर्मा, पिता-काशी शर्मा, साकिन चौसा, थाना-पानापुर, जिला-सारण।

छापामारी दल में शामिल सदस्य

थानाध्यक्ष महिला/मढ़ौरा / खैरा/तरैया/अमनौर थाना एवं अन्य पदाधिकारी/कर्मी।

मिशन मुक्ति फाउन्डेशन के सदस्य।

रेस्कयू फाउन्डेशन, दिल्ली के सदस्य।

नारायणी सेवा संस्थान, सारण के सदस्य।

रेस्कयू एण्ड रिलीफ फाउन्डेशन, पश्चिम बंगाल ।

उल्लेखनीय है की सारण पुलिस द्वारा “आवाज दो” अभियान चला कर महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ लगातर कार्रवाई की जा रही है। जनता से सुचना और सहयोग की अपील है यदि आप या आपके आसपास कोई महिला इस तरह की समस्याओं से जुझ रही है, तो “आवाज दो” हेल्पलाईन नं0-9031600191 से अपनी बात हम तक पहुँचाएं।

Univarta

आर्केस्ट्रा में काम करने वाली 21 नर्तकियां मुक्त

https://www.univarta.com/news/bihar-jharkhand/story/3484568.html

राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jun 7 2025 9:11PM

सारण : आर्केस्ट्रा में काम करने वाली 21 नर्तकियां मुक्त

छपरा, 07 जून (वार्ता) बिहार में सारण जिले की पुलिस ने शनिवार को आर्केस्ट्रा में काम करने वाली 21 नर्तकियों को मुक्त कराया है।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त सूचना के आधार पर मिशन मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली, नारायणी सेवा संस्थान छपरा एवं रेस्क्यू फाउंडेशन पश्चिम बंगाल के साथ आवाज दो टीम के द्वारा जिले के मढौरा, खैरा, तरैया एवं अमनौर थाना क्षेत्र में टीम बनाकर छापेमारी की गई। इस दौरान 21 नाबालिक नर्तकियों को मुक्त कराया गया, जिसमें 15 पश्चिम बंगाल की रहने वाली है,जबकि तीन आसाम, एक उत्तर प्रदेश एवं दो बिहार की रहने वाली हैं।

विस्तृत समाचार के लिए हमारी सेवाएं लें।.